University in News on 10 June 2021

University of Lucknow | Centenary Year
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी वर्ष

100 Years 1920-2020

AMAR UJALA MY CITY PAGE 5

डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों ने की पीएचडी कराने की वकालत

माई सिटी रिपोर्टर

■ विवि की पांच सदस्यों और शिक्षकों की बैठक में रखा पक्ष

लखनऊ। लविवि से संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों ने उनको भी पीएचडी कराने का अवसर दिए जाने की पुरजोर वकालत की है। बुधवार को महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा शोध करवाने की संभावना को लेकर गठित विवि की पांच सदस्यों और शिक्षकों की बैठक में उन्होंने यह पक्ष रखा। बैठक में विवि में शामिल किए गए चार नए जिलों के कॉलेजों के शिक्षक भी शामिल रहे।

लविवि के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने पांच सदस्य समिति का गठन किया है, जिसमें डीन एकेडमिक्स प्रो. राकेश चंद्रा, डीएसडब्लू पूनम टंडन, व्यापार प्रशासन विभाग से डॉ. संगीता साहू, नेताजी सुभाष राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. अनुराधा तिवारी और डीएवी डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अंजनी मिश्रा समेत शामिल हैं। कमेटी का उद्देश्य डिग्री कॉलेजों द्वारा पीएचडी करवाने की संभावना को तलाशना है। डिग्री कॉलेजों के सभी शिक्षकों ने मांग रखी कि विवि शोध संबंधी रणनीति में बदलाव लाए। जो नए जिलों के कॉलेज जुड़े हैं उनके शिक्षकों ने बताया कि वे पहले से ही शोध करवाते आ रहे हैं। लविवि में शामिल होने के बाद से वे इससे वंचित नहीं रहना चाहते।

प्रो. अवधेश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

लखनऊ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर अवधेश त्रिपाठी को महाराष्ट्र नवी मुंबई के ठाणे में आदर्श भारत सोशल फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। उनको यह सम्मान उनके असाधारण कौशल, समर्पण और व्यावसायिकता के सम्मान में प्रदान किया गया है। पुरस्कार प्रदान करते हुए संस्था ने प्रो. त्रिपाठी के समाज और देश के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की है। विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के साथ प्रो. अवधेश त्रिपाठी वर्तमान में अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, लखनऊ विश्वविद्यालय की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। (माई सिटी रिपोर्टर)

JAGRAN CITY PAGE I & 7

'लखनऊ विश्वविद्यालय शोध नीति में लाए बदलाव'

जागरण संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय को अपनी शोध की नीति में बदलाव करना चाहिए। इससे न केवल महाविद्यालयों को लाभ होगा, बल्कि विश्वविद्यालय भी देश और विश्व भर में अपने शोध की गुणवत्ता को और निखार पाएगा। यह सुझाव महाविद्यालयों में स्नातक शिक्षकों के लिए शुरू किए जाने वाले शोध को लेकर आखिरी दिन बुधवार को हुई आनलाइन बैठक में शिक्षकों ने दिए। आए हुए सभी सुझावों पर मंथन कर कमेटी 15 जून तक अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंपेगी।

बैठक में कई शिक्षकों ने बताया कि वह लविवि की शोध न करा पाने की नीति की वजह से निजी कर्म क्षेत्र में पीछे रह गए। उन्हें किसी न किसी बड़े अवसर से हाथ धोना पड़ा। सभी ने इच्छा जताई की विश्वविद्यालय शोध संबंधी अपनी नीति में बदलाव लाए। बैठक में लविवि से जुड़े नए चार जिलों के महाविद्यालयों के शिक्षकों ने भी शामिल होकर इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। कहा कि विश्वविद्यालय से जुड़ने से पहले वह शोध करवाते आ रहे हैं और विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद वे छात्रों को शोध करवाने से वंचित नहीं रहना चाहते। शिक्षकों का कहना था कि आज के वैश्विक परिवेश और इंटरनेट की उपस्थिति में संसाधन की कमी रिलेटिव मात्र रह गई है। सभी ने छात्र हित व शोध हित में महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को भी शोध करवाने का अवसर देने का समर्थन किया। बैठक में डीन एकेडमिक्स प्रो. राकेश चंद्रा, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. पूनम टंडन, व्यापार प्रशासन विभाग से डा. संगीता साहू और अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

दैनिक जागरण ने यह मौका दिया कि हम कोरोना के कारण दिवंगत लोगों को याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें। साथ ही कोरोना की चोट झेल रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें। जो चला गया, वह वापस नहीं आ सकता। जो बचे हैं, उन्हें बचाए रखना हम सब का दायित्व है। सतर्क, सक्रिय और सुरक्षित रहें।

– प्रो. आलोक कुमार राय, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय

मुकुल श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जन संचार, लविवि ● **सौ. स्वयं**

AMRIT VICHAR PAGE 2

विश्वविद्यालय शोध संबंधी अपनी नीति में बदलाव लाएं

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक के शिक्षकों को शोध कराने के उद्देश्य से तीन दिवसीय बैठक में बुधवार को अंतिम दिन महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ बैठक हुई। इस बैठक के दौरान शिक्षकों ने विश्वविद्यालय की नीति को बदलने पर जोर दिया। साथ ही शोध न करा पाने के कारण आए अवरोध की भी चर्चा की। शिक्षकों ने बैठक में अपनी आपबीती साझा की। सभी ने एक स्वर में यह इच्छा जताई कि विश्वविद्यालय शोध संबंधी अपनी नीति में बदलाव लाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय से हाल ही में जुड़े नए चार जिलों के महाविद्यालयों के अध्यापक भी इस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने भी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया।

PIONEER PAGE 4

एलयू की शोध पॉलिसी का नए जुड़े चार जिलों के कॉलेजों ने किया स्वागत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पीजी कालेजों में शोध के संभावनाओं की तलाश को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आलोक कुमार राय की तरफ से गठित पांच सदस्यीय टीम ने बुधवार को विवि के सीमा विस्तार के बाद जुड़े चार नए जिलों रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर के कॉलेजों के साथ बैठक की। बैठक में कालेजों ने विवि की पहल का स्वागत करते हुए बताया कि वे पहले से शोध कराते चले आ रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के शोध को बढ़ावा देने के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए गठित समिति की आज 3 दिन से चल रहे बैठकों का सिलसिला संपन्न हुआ। जहां दो दिन पहले विश्वविद्यालय के सभी विभागों के अध्यक्षों, समन्वयकों एवं संकायाध्यक्षों के साथ फिर मंगलवार को विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य की एक बैठक आहूत की गई। बैठक में कई अध्यापकों ने उपस्थित जनों के साथ अपनी आपबीती साझा की जिसमें वह शोध ना करा पाने के विश्वविद्यालय के पॉलिसी की वजह से निजी कर्म क्षेत्र में पीछे रह गए या उन्हें किसी न किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ा। सभी ने एक स्वर में यह इच्छा जताई की विश्वविद्यालय शोध संबंधी अपनी पॉलिसी में बदलाव लाएं और यह आशा जताई कि इससे न केवल महाविद्यालय का भला होगा बल्कि विश्वविद्यालय भी देश और विश्व भर में अपने शोध की गुणवत्ता को और भी निखार पाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय से हाल ही में जुड़े नए चार जिलों के महाविद्यालयों के अध्यापक भी इस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने भी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। सभी ने इस बात का भी समर्थन किया कि नई शिक्षा नीति के आने के बाद विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए।

विवि परीक्षाओं को लेकर एलयू की परीक्षा समिति की बैठक आज

● परीक्षा को लेकर तय होगी रूपरेखाए प्रश्न पत्र के स्वरूप पर होगा निर्णय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूजी व पीजी की परीक्षाओं को लेकर शासन स्तर पर स्थिति स्पष्ट किये जाने के बाद निर्णय लेने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने गुरुवार को परीक्षा समिति की बैठक बुलाई है। समिति की बैठक में तय होगा कि अंतिम वर्ष के साथ दूसरे साल की परीक्षाओं का स्वरूप क्या होगा। ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन या फिर ओएमआर शीट आधारित होगी। शासन स्तर पर विश्वविद्यालयों को अगस्त मध्य तक परीक्षा कराने के साथ ही 31 अगस्त तक परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे 13 सितंबर से शैक्षणिक सत्र 2021.22 का संचालन हो सके। शासन स्तर पर विश्वविद्यालयों को लेकर एक स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि प्रायोगिक परीक्षा के अंक लिखित परीक्षा से प्राप्त अंक के आधार पर तय होंगेए इससे काफी राहत मिली है। विवि के प्रवक्ता प्रो दुर्गेश श्रीवास्तव का कहना है कि शासन स्तर पर जारी निर्देश के आधार पर निर्णय लेने के लिए कल परीक्षा समिति की बैठक बुलाई गई गई। जिसमें सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।